

प्रेषक,

अनिता श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।

कार्मिक अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 28 मार्च, 2018

विषय :-सरकारी सेवकों में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्मिक अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- 3/2017/13(1)2007 /का-1-2017, दिनांक 06.07.2017, शासनादेश संख्या-9/2017/13(1)2007/का-1-2017, दिनांक 08.09.2017 एवं शासनादेश संख्या-11/2017/13(1)2007/का-1-2017, दिनांक 16.10.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त संदर्भित शासनादेशों द्वारा अपने-अपने विभाग के अधिष्ठातीय नियंत्रणाधीन समस्त कार्मिकों के सम्बन्ध में अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग की नियमानुसार कार्यवाही क्रमशः दिनांक 31.07.2017, दिनांक 15.09.2017 एवं दिनांक 31.10.2017 तक पूर्ण कराकर कृत कार्यवाही की सूचना शासनादेश दिनांक 26.10.1985 में निर्धारित प्रारूप पर कार्मिक अनुभाग-1 को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी, परन्तु उक्त वांछित संकलित सूचना अभी भी अधिकांश विभागों द्वारा कार्मिक अनुभाग-1 को उपलब्ध नहीं करायी गयी है ।

3- अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अनिवार्य सेवानिवृत्ति सम्बन्धी स्क्रीनिंग की कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण कराकर अपने-अपने विभाग की अद्यतन सम्पूर्ण संकलित सूचना, (जिसमें दिनांक 18.03.2018 एवं दिनांक 19.03.2018 को दूरभाष एवं अन्य इलेक्ट्रानिक्स माध्यम से उपलब्ध करायी गयी सूचना भी सम्मिलित हो) अपने हस्ताक्षर से निर्धारित प्रारूप पर (क्षेत्रीय स्तर से अथवा एक ही विभाग के भिन्न-भिन्न अनुभाग के स्तर से प्राप्त सूचनार्ये अनुश्रवण हेतु ग्रहणसंकलित नहीं की जायेगी) कार्मिक अनुभाग-1 को दिनांक 02.04.2018 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

संलग्नक : यथोक्त ।

भवदीय,
अनिता श्रीवास्तव
विशेष सचिव ।

अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु की गई स्क्रीनिंग से सम्बन्धित वार्षिक सूचना
वर्ष 2017-2018

क्रमांक	कार्मिकों की श्रेणी	50 वर्ष की आयु प्राप्त कार्मिकों की कुल संख्या	स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष विचारार्थ रखे गये कार्मिकों की कुल संख्या	कार्मिकों की कुल संख्या जो स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति के योग्य समझे जायं	अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किये गये कार्मिकों की कुल संख्या	स्क्रीनिंग कमेटी के विचार से सहमत न होने के संक्षिप्त कारण	स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रखे बिना नियुक्त प्राधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किये गये कार्मिकों की कुल संख्या, यदि कोई हो	अन्य विवरण यदि कोई हो,
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	विभागाध्यक्ष/अतिरिक्त विभागाध्यक्ष-							
2	पी0सी0एस0 संवर्ग-							
	(क) श्रेणी "क" के अधिकारी-							
	(ख) श्रेणी "ख" के अधिकारी-							
3	पी0सी0एस0 संवर्ग से भिन्न अधिकारी-							
	(क) श्रेणी "क"							
	(ख) श्रेणी "ख"							
4	श्रेणी "ग"							
5	श्रेणी "घ"							
योग								

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।